

प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का वसितार

प्रलिस के लयः

ईईजेड, प्रशांत महासागर, इंडो-पैसफिक, क्वाड, ब्लू अर्थव्यवस्था ।

मेन्स के लयः

प्रशांत द्वीप समूह के देश और इसका महत्त्व, भारत-पीआईसी संबंध, वैश्विक समूह ।

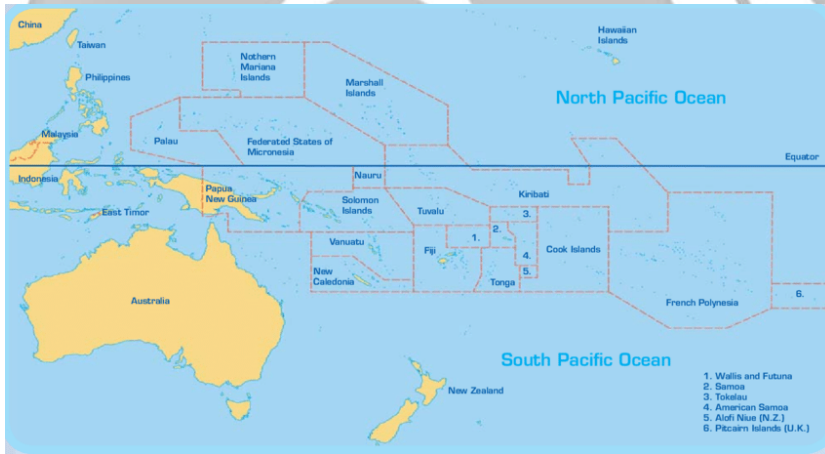
चर्चा में क्यों?

चीन के वदेश मंत्री वर्तमान में **दस प्रशांत द्वीपीय देशों (PIC) की यात्रा पर हैं** और उन्होंने फ़िजी के साथ दूसरी चीन-प्रशांत द्वीपीय देशों के वदेश मंत्रियों की बैठक की सह-मेज़बानी की है ।

- हालाँकि, बैठक में एक व्यापक रूपरेखा समझौते को आगे बढ़ाने के संदर्भ में **चीन और PICs के बीच आम सहमति नहीं बन पाई** ।
- अप्रैल 2022 में चीन ने **सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक वविदासपद सुरक्षा समझौते** पर हस्ताक्षर किये जसिने कषेत्रीय चलिओं को बढ़ाया ।

प्रशांत द्वीपीय देशः

- प्रशांत द्वीप देश 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उषणकटबिधीय कषेत्र से संबंधित है ।
- इनमें कुक आइलैंड्स, फ़िजी, करिबिती, रपिब्लिक ऑफ मारशल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (FSM), नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं ।



PIC का महत्त्वः

- **सबसे बड़ा अनन्य आर्थिक कषेत्र (EEZ):**
 - द्वीपों को भौतिक और मानव भूगोल के आधार पर तीन अलग-अलग भागों में वभिजति कया गया है **माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलनेशिया** ।
 - अपने छोटे भूमि कषेत्र के बावजूद **द्वीप प्रशांत महासागर के वसित कषेत्र में फैले हुए हैं** ।
 - हालाँकि इनमें से कुछ सबसे छोटे एवं सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं, जिनके पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े **अनन्य आर्थिक कषेत्र (EEZ)** ।

हैं।

■ आर्थिक क्षमता:

- बड़े EEZ में बहुत अधिक आर्थिक संभावनाएँ हैं क्योंकि उनका उपयोग मत्स्य पालन, ऊर्जा, खनजिों और वहाँ मौजूद अन्य समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिये किया जा सकता है।
 - इसलिये ये छोटे द्वीप राज्यों के बजाय बड़े महासागरीय राज्यों के रूप में पहचाने जाते हैं।
- वास्तव में करिबिाली और FSM दोनों PIC का EEZ भारत से बड़ा है।

■ प्रमुख शक्ति प्रतदिवंद्वति में भूमिका:

- इन देशों ने सामरिक क्षमताओं के विकास और प्रदर्शन के लिये शक्ति प्रक्षेपण और प्रयोगशालाओं के लिये स्केपरिगि बोरड्स रूप में प्रमुख शक्ति प्रतदिवंद्वति में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिआई है।
- औपनिवेशिक युग की प्रमुख शक्तियों ने इन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिये एक दूसरे के साथ प्रतस्पर्धा की।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान (शाही जापान और यूएस) प्रशांत द्वीपों ने भी संघर्ष के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में काम किया।

■ प्रमुख परमाणु हथियार परीक्षण स्थल:

■ संभावति वोट बैंक:

- साझा आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं द्वारा संबंधति 14 PICs संयुक्त राष्ट्र में मतदान के लिये ज़िम्मेदार हैं और अंतरराष्ट्रीय राय जुटाने हेतु प्रमुख शक्तियों के संभावति वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।

चीन के लिये PICs का महत्त्व:

■ एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बनने में:

- PICs चीन के समुद्री हति और नौसैनिक शक्ति के वसितार की प्राकृतिक रेखा में अवस्थति हैं
- वे चीन की 'प्रथम द्वीप शृंखला' से परे स्थति हैं, जो देश के समुद्री वसितार के प्रवेश बट्टि का प्रतनिधितिव करता है।
- PICs भू-रणीतक दृष्टि से उस स्थान पर अवस्थति हैं जसि चीन अपने 'सुदूर समुद्र' के रूप में संदर्भति करता है, जसिका नियंत्रण चीन को एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बना देगा - जो महाशक्ति बनने के लिये एक आवश्यक शर्त है।

■ काउंटरगि क्वाड:

- PICs को प्रभावति करने की आवश्यकता ऐसे समय में चीन के लिये और भी अधिक दबाव का वषिय बन गई है जब चीन के वरिध स्वरुप हदि-प्रशांत में चतुरभुज सुरक्षा वार्ता एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है।

■ ताइवान की भूमिका:

- PICs की विशाल समुद्री समृद्धि के अलावा, ताइवान चीन के प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका नभिता है।
- चीन, ताइवान को इस क्षेत्र में एक प्रतस्पर्धी मानता है तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी मान्यता का वरिध करता है।
- इसलिये जसि भी देश को चीन के साथ आधिकारिक रूप से संबंध स्थापति करने होंगे, उसे ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे।
 - चीन अपनी आर्थिक उदारता के माध्यम से 14 PICs में से 10 से राजनयिक मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।
 - केवल चार PICs - तुवालु, पलाऊ, मार्शल द्वीप और नौरु, वर्तमान में ताइवान को मान्यता देते हैं।

चीन के वर्तमान कदम के नहितारथ:

■ PICs को प्रमुख शक्ति संघर्षों में शामिल कर सकता है:

- सामूहिक रूप से PICs चीन के व्यापक और महत्वाकांक्षी प्रस्तावों से सहमत नहीं थे, इसलिये चीन समझौते पर आम सहमतप्राप्त करने में वफिल रहा।
- चीन द्वारा प्रस्तावति आर्थिक और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से PICs की संप्रभुता और एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा भवषिय में उन्हें बड़े शक्ति संघर्षों में शामिल किया जा सकता है।

■ क्षेत्र में पारंपरिक शक्तियों को मज़बूत करने में:

- प्रशांत द्वीपों के प्रतचीन की कूटनीतिकी तीव्रता ने उन शक्तियों को मज़बूत बना दिया है जिन्होंने परंपरागत रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय गतशीलता को नियंत्रति किया है।
- चीन-सोलोमन द्वीप समझौते के बाद से अमेरिका ने इस क्षेत्र के लिये अपनी कूटनीतिकी प्राथमिकता पर फरि से वचिार करना शुरू कर दिया है।
- चीन के प्रस्तावति सौदे के खिलाफ वपिक्ष को लामबंद करने में अमेरिका द्वारा नभिआई गई भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि **संघीय राज्य माइक्रोनेशिया (FSM)** एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को मान्यता देता है और साथ ही अमेरिका के साथ मुक्त संघ के समझौते का भी हसिसा है।
 - संघीय राज्य माइक्रोनेशिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थति एक द्वीपीय देश है जसिमें 600 से अधिक छोटे-छोटे द्वीप शामिल हैं।

भारत तथा प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच संबंधों की मुख्य वशिषताएँ:

■ परचिय:

- प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की बातचीत अभी भी काफी हद तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय डायस्पोरा की उपस्थति से प्रेरति है।
 - फजी की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और लगभग 3000 भारतीय वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में रह रहे हैं।

- संस्थागत जुड़ाव के संदर्भ में, भारत प्रशांत द्वीप मंच (PIF) में प्रमुख संवाद भागीदारों के रूप में भाग लेता है।
- हाल के वर्षों में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की बातचीत को सुवर्धित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास के रूप में प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) के लिए एक कार्रवाई-उन्मुख मंच का गठन किया गया है।
 - FIPIC की शुरुआत वर्ष 2014 में एक बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में की गई थी।

सहयोग के क्षेत्र:

■ ब्लू इकॉनमी:

- अपने संसाधन संपन्न अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) के साथ प्रशांत द्वीपीय देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तरल प्राकृतिक गैस (LNG) और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आकर्षक स्रोत होने के साथ-साथ इनके लिए नए बाजार भी प्रदान कर सकते हैं।
- 'ब्लू इकॉनमी' के विचार पर जोर देते हुए भारत इन देशों के साथ विशेष रूप से जुड़ सकता है।

■ जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:

- इन द्वीप देशों का भूगोल उन्हें जलवायु चुनौतियों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
 - समुद्र जलस्तर में वृद्धि के कारण बढ़ती मट्टी की लवणता नचिले द्वीपीय राज्यों के लिए खतरा है, जिससे वसिस्थापन की समस्या भी पैदा हो रही है।
- इसलिये, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्रभावी और ठोस समाधान के लिए एक करीबी साझेदारी विकसित की जा सकती है।

■ आपदा प्रबंधन:

- प्रशांत द्वीप समूह के अधिकांश देश व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं।
- भारत आपदा जोखिम लचीलापन की क्षमता निर्माण में सहायता कर सकता है।
- सितंबर, 2017 में, भारत ने सात प्रशांत द्वीपीय देशों में जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है।

आगे की राह:

- प्रशांत द्वीपीय देश भौगोलिक रूप से छोटे होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में काफी आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक महत्त्व रखते हैं।
- इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के हालातिया प्रयासों ने भारत को इन देशों के बहुत करीब ला दिया है।
- प्रशांत द्वीपीय देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण साझा मूल्यों और साझा भविष्य के आधार पर क्षेत्र के साथ एकमतदर्शी, आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण और समावेशी संबंधों पर केंद्रित है।
- आने वाले वर्षों में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत का जुड़ाव तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन के जल्द ही होने की उम्मीद है।

स्रोत: द हिंदू